पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International 1983-2023

हमारा मुख-पत्र वर्ष 24 , अंक 4/2023

सवालिया समाज का हो गठन, इससे आएगा सुशासन

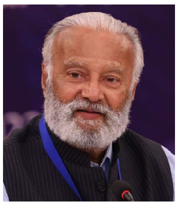

पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भारत के सच्चे सपूत थे। विपक्ष भी उनकी सोच का लोहा मानता था। जब बोलते थे तो सभी मंत्र मुग्ध हो जाते थे। निर्विवाद और साफ सुधरी छवि रही उनकी । सदैव देश हित में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया उन्होंने। शांति और शक्ति के प्रतीक थे वह। पोकरण में परमाणु परीक्षण कर उन्होंने पूरे विश्व को चौंका दिया था। भारत परमाणु सम्पन्न देश बन गया। अनंत प्रतिभाओं के धनी थे अटलजी । निर्मल और स्वच्छन्द स्वभाव उनकी खासियत थी....।

देश में हर साल उनकी जयंती पर 25 दिसम्बर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। मुझे वह दिन याद आए बिना नहीं रहता जब वर्ष 1983 में पहली बार अटलजी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । 'ग्राम गदर' भित्तीपत्र का पहला अंक लेकर मैं उनके पास गया था। मैं देखता रहा, बड़ी तल्लीनता से उन्होंने 'ग्राम गदर' को पढ़ा। उन्होंने पूछा तो मैंने बताया था राजस्थान के दूर दराज के गांवों तक समाचार पत्र नहीं पहुंचते। इससे गांव के लोगों को उनके लिए बनाई गई योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती। जिससे वे योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। यह भित्तीपत्र डाक द्वारा भेजा जा रहा है। डाक विभाग के ई.डी. कर्मचारी (ग्रामीण पोस्टमैन) स्वेच्छा से गांव की चौपाल पर इसे चिपकाते हैं और पढ़े-लिखे गांव के लोग इसे पढ़कर सुनाते हैं। गांव वाले इससे जागरूक होंगे। यह सब सुनकर उन्होंने खुशी जाहिर की और कहा था 'सवालिया समाज का गठन इसका खास मकसद होना चाहिए... यह नेक काम है, इससे शासन प्रशासन में सुशासन आएगा'।

प्रसन्नता है कि प्रदेश में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनता से वादा किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के विजन पर चलते हुए 'सरकार गुड गवर्नेंस' देगी। सरकार मंत्रियों-अधिकारियों से मिलकर बनती है। अकसर सामने आता है कि ये जिम्मेदार ही अपने दायित्वों से कन्नी काटते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। निगरानी ऐसी हो कि जनता के धन का लाभ अपात्र लोग न उठा पाएं। प्रदेश में राजस्व बढ़ाने, वित्तीय अनुशासन अपनाने एवं प्रशासनिक सुधारों के साथ नौकरशाही को अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनाना बेहद जरूरी है। जितना वित्तीय संसाधनों को समय पर जुटाना जरूरी है, उतना ही जरूरी यह भी है कि उन्हें दक्षता के साथ योजनाबद्ध तरीके से खर्च किया जाए। जनता का पैसा जो राजकोष में आता है वह बेवजह खर्च नहीं हो, यह सुशासन का मूल मंत्र होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि सरकार की योजनाएं पोस्टर बनाने के लिए नहीं है, सरकार की ओर से खर्च किए जा रहे प्रत्येक रुपए का लाभ जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों को मिलना चाहिए ।

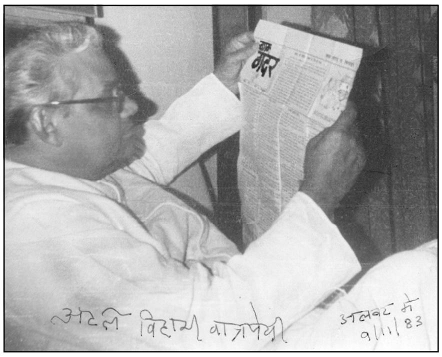

प्रदेश में नई सरकार से अपेक्षा है कि वह किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए न केवल कृषि कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारे, बल्कि ऐसी व्यवस्था भी करे जिससे किसानों के उत्पाद को उचित मूल्य मिले। यह क्षेत्र करीब 12 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। ऐसे प्रयास भी हो जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि रोजगार जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प इत्यादि का उचित वातावरण बनें। सामाजिक और आर्थिक विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र (एमएसएमई) का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लोगों को रोजगार देने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इससे रोजगार की तलाश में गांवों से पलायन की समस्या भी दूर हो सकेगी ।

नई सरकार के सामने महंगाई-बेरोजगारी और कर्ज... सबसे बड़ी चुनौती होगी । इससे निपटने के लिए राजस्व बढ़ाने के इंतजाम भी करने होंगे। प्रदेश की जनता को भरोसा है कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास में नव निर्वाचित सरकार कोई कसर नहीं रहने देगी और जनमानस में अपनी अच्छी छवि उजागर करेगी ।

प्रदीप एस महता
महामंत्री, कट्स इंटरनेशनल

इस अंक में...

पीएम आवास योजना में राज्य पिछड़ा 3
काले धन के मकड़जाल को तोड़ना कठिन ... 5
देश की अर्थव्यवस्था में तेज वृद्धि 7
भारत में भूजल खतरनाक स्तर पर 9
हर महिला हो सबला और सशक्त 10

जनता की शक्ति से ही मिलता है सरकार को अधिकार! इसे कायम रखने के लिए आप हैं जिम्मेदार!!

किचन गार्डन विकसित करने से सुधरता है स्वास्थ्य एवं पर्यावरण

घरों में किचन गार्डन विकसित करने से मानव स्वास्थ एवं पर्यावरण को लाभ प्राप्त होता है। जैविक सब्जियां स्वास्थ्य वर्धक एवं रसायन मुक्त होती है। यह विचार 'कट्स' इंटरनेशनल तथा हरदेव शिक्षण एवं जनकल्याण संस्थान द्वारा 6 अक्टूबर 2023 को जयपुर में आयोजित कम्युनिटी स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन बैठक में शिक्षाविद भूपराम शर्मा ने व्यक्त किए।

बैठक में 'कट्स' के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी अमरदीप सिंह ने उपस्थित महिलाओं को शेयरिंग कम्यूनिटी के लाभ तथा पर्यावरण की सुरक्षा के गुण सूत्र बताते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने को प्रेरित किया। महिलाओं के द्वारा कबाड़ से जुगाड़ कार्यक्रम के अंतर्गत पुराने कपड़ों से पायदान, बैग, प्लास्टिक की बोतलों से गुलदस्ते, फूल, झालर और गमले इत्यादि बनाई हुई उपयोगी वस्तुओं की सभी ने सराहना की। कलाकार सृजन मिश्रा द्वारा महिलाओं से पर्यावरण संबंधी, प्राचीन संस्कृति एवं परंपराओं को कायम रखने, नवीन विचारों को जानने और जीवन में उपयोग में लाने के लिए कला के माध्यम से प्रेरित किया गया।

समाजसेविका श्रीमती मंजू राठौड़ द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाली सुमन शर्मा, मधु शर्मा, पूजा यादव, रीटा देवी, संगीता कटेवा, दीपा राठौड़, कांता गुर्जर, मीना बैरवा इत्यादि महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए सम्मानित किया गया तथा सहयोग के लिए नाउ न्यूज चैनल से शत्रुंजय सिंह, हरिश्चंद्र शर्मा, हरि कृष्ण शर्मा एवं प्रेमचंद बैरवा को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के पश्चात सभी संभागीय महिलाओं को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की सलाह देते हुए कपड़े के बैग दिए गए।

सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने को किया प्रेरित

महिलाओं की ओर से अपने घरों में किचन गार्डन लगाने से परिवार स्वस्थ बन रहे हैं, साथ ही इससे पर्यावरण संवर्धन में सहयोग मिल रहा है। यह विचार 'कट्स' प्रतिनिधि धर्मेन्द्र चतुर्वेदी ने 6 नवम्बर 2023 को जयपुर में 'कट्स' इंटरनेशनल एवं विकासोन्मुख संस्थान द्वारा आयोजित कम्युनिटी स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन बैठक में प्रस्तुत किए।

परियोजना कॉर्डिनेटर राजदीप पारीक ने महिलाओं को शेयरिंग कम्युनिटी के लाभ गिनाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर महिलाओं ने कबाड़ से जुगाड़ ट्रेनिंग के तहत पुराने कपड़ों से बनाए गए पायदान, बैग, गुलदस्ते, फूलमाला, गमले और झालर इत्यादि की प्रदर्शनी भी लगाई। बैठक में सृजन मिश्रा द्वारा महिलाओं को पर्यावरण संवर्धन, प्राचीन संस्कृति एवं परंपराओं को कायम रखने के लिए नवीन विचारों को जानने और जीवन में उपयोग में लाने के लिए कला के माध्यम से प्रेरित किया गया।

संस्थान सचिव राजेश मालाकार ने बताया कि यह गतिविधियां ग्रीन एक्शन वीक 2023 के तहत आयोजित की जाकर संस्था की महिला विंग कॉर्डिनेटर शारदा सैनी के नेतृत्व में महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। इस अवसर पर किचन गार्डन में बेहतर प्रदर्शन करने वाली 25 महिलाओं को प्रमाण-पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। होली फेथ एकेडमी जगन्नाथपुरी के प्रिंसिपल मधु पाठक ने आंगतुकों का आभार व्यक्त किया।

डिजिटल लेनदेन व ऑनलाइन शॉपिंग के मामलों में जागरूकता आवश्यक

'कट्स' मानव विकास केंद्र एवं जिला रसद कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में रावला सेंती में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर ई-कॉमर्स और डिजिटल व्यापार के युग में उपभोक्ता सरंक्षण विषय पर जिला स्तरीय विचार गोष्ठी हुई।

मुख्य अतिथि महेन्द्र कुमार डूडी, जिला विकास प्रबंधक (नाबार्ड) ने कहा कि उपभोक्ता जागरूकता के अभाव में ठगी का शिकार हो रहा है। उपभोक्ता को अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहकर डिजिटल लेनदेन व ऑनलाइन शॉपिंग के मामलों में ज्यादा जागरूक रहने की आवश्यकता है। केंद्र समन्वयक गौहर महमूद ने ई-कॉमर्स पर ऑनलाइन मार्केटिंग में उपभोक्ताओं के साथ हो रही ठगी की जानकारी दी। सत्येन्द्र प्रकाश मेहता सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं रसद विभाग के मनीष कुमार जाजू ने विभाग द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। गोष्ठी में 40 महिलाओं सहित 52 लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन मदनगिरी गोस्वामी ने किया एवं आभार व्यक्त 'कट्स' के गायत्री मौड ने किया।

जल जीवन मिशन में हुए घोटाले

सरकार बदलते ही जल जीवन मिशन में हुए घोटालों की पोल खुलने लगी है। अब जमीन में बिछाए गए लोहे के पाइप की जगह प्लास्टिक के पाइप बाहर आने लगे हैं। योजनाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच में भ्रष्टाचार की परतें उधड़ना शुरू हो चुका है।

जयपुर में बस्सी और तुंगा क्षेत्र के गांवों में 34 किलोमीटर की पाइपलाइन तो कागजों में ही बिछा दी गई। जांच में पता लगा कि लाइन तो सिर्फ 5 किमी तक ही बिछी है और ठेकेदारों को करोड़ों रुपए का भुगतान भी कर दिया गया। बस्सी तुंगा ब्लॉक के कई गांवों में भी गड़बड़ियां सामने आई है। प्रदेश के सभी जिलों में जांच हो तो इंजीनियरों व ठेकेदारों की मिलीभगत से हुए करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार सामने आ सकता है।

(रा.प., 18.12.23, 21.12.23)

शहरी सरकार का बजट जन से दूर

जयपुर हैरिटेज निगम बोर्ड बने तीन साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन बजट के लिए एक बार ही सत्र बुलाया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 और 23-24 में बिना बजट पारित किए ही राज्य सरकार को भेज दिया गया। ग्रेटर निगम की भी स्थिति अलग नहीं है। तीन वर्ष में बजट के लिए एक बार ही सत्र बुलाया गया। बजट में जो घोषणाएं की गई उन्हें पूरा करने के लिए पैसे की कमी आ रही है।

हैरानी की बात यह है कि इस वित्तीय वर्ष में राजधानी के दोनों नगर निगम ने दो हजार करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया है। लेकिन कौन सा पैसा किस मद में खर्च हो रहा है, इसकी जानकारी जनता को नहीं है।*(रा.प., 25.12 23)*

पीएम आवास योजना में राज्य पिछड़ा

राज्यों के लिए शहरी आबादी को सस्ते मकान दिलाने के लिए चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान की प्रगति काफी कमजोर रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार टॉप 20 राज्यों में राजस्थान 14वें नंबर पर है। जबकि पिछली भाजपा सरकार के समय 8 साल पहले राजस्थान पहले स्थान पर था।

आवास योजना की हाउस फॉर ऑल स्कीम के तहत देश में शहरी लोगों को 78.27 लाख आवास बना कर सुपुर्द किए गए, जबकि 5 साल में राजस्थान में सिर्फ 1.75 लाख आवास ही सुपुर्द किए गए। यह कुल आवासों का मात्र 2.23 प्रतिशत है।

इसके साथ ही पूरे देश में स्वीकृत आवासों में कंपलीट करके लोगों को हस्तांतरित करने में भी राजस्थान फिसड्डी रहा है। राजस्थान को 2 लाख 89 हजार 446 आवास स्वीकृत किए गए। उनमें से सिर्फ 1 लाख 75 हजार 561 आवास ही पूरे बना कर लोगों को दिए गए।

(दै.भा., 08.12.23)

कीटनाशक बिगाड़ रहे लोगों की सेहत

प्रदेश में अलवर सहित तिजारा और भिवाड़ी के दूध और पानी में आर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक की मात्रा सर्वाधिक मिली है, जो कि सेहत के लिए घातक है। इससे कैंसर, ऑप्टिज्म जैसी कई गंभीर बीमारी हो सकती है। इन क्षेत्रों में दूध और पानी के लगभग 200 सैंपल लिए गए जिनकी जांच में इसकी पुष्टि हुई है।

इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि यहां पर खेतों में पैदावार को कीटों से बचाने और जल्द पैदावार बढ़ाने के लिए कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल अधिक किया जा रहा है। इससे यहां उपजाऊ भूमि खराब हो रही है। सर्वे पूरा होने के बाद रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी और आर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक पर रोक लगाने की पहल की जाएगी। *(रा.प., 04.10.23)*

'शुद्ध के लिए युद्ध' पर सवालिया निशान

खाद्य पदार्थो में मिलावट रोकने के लिए चलाया जा रहा 'शुद्ध के लिए युद्ध अभियान' पर सवालिया निशान लग गया है। फूड सेफ्टी एनफोर्समेंट एक्ट के तहत बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और झुंझुनूं के खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से नमूने लेने में अव्वल रहा है, जबकि बीकानेर, नागौर, जयपुर-2 और धौलपुर जिलों के खाद्य सुरक्षा अधिकारी नमूने लेने में पीछे हैं।

इसी तरह से बिना एक्ट के तहत लिए गण नमूनों में जैसलमेर, बूंदी,जालौर और अजमेर की स्थिति एक्सीलेंट और अलवर, जयपुर-2, सिरोही और पाली जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीछे हैं। जबकि अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरो पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। *(दै.भा., 04.11.23)*

जिम्मेदार भूले गरीबों का गेहूं उठाना

केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए खाद्य सुरक्षा योजना लाभार्थियों के राशन का पूरा कोटा जारी किया। उसमें से प्रदेश के खाद्य विभाग के अधिकारी भारतीय खाद्य निगम के डीपो से 1.93 लाख मीट्रिक टन गेहूं उठाना ही भूल गए।

वर्ष 2019 से दिसंबर 2022 तक जितना कोटा जारी किया गया, उसमें से राज्य के खाद्य विभाग ने 1.93 लाख मीट्रिक टन गेहूं कम उठाया। गेहूं के कम उठाव के लिए विभाग के बड़े अधिकारी जिम्मेदार हैं। लेकिन अब सब चुप्पी साधे बैठे हैं। राशन की दुकानों पर कम गेहूं पहुंचने पर राशन डीलर गरीबों को टालते रहे। इससे पूरे राज्य में 4 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को राशन का गेहूं कम मिला। अब विभाग के अधिकारी गेहूं का पूरा उठाव बता कर अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करने में लगे हैं। *(रा.प., 05.12.23)*

गरीबों का गेहूं हो गया गायब

खाद्य विभाग के अफसरों और ठेकेदारों के गठजोड़ से जयपुर जिले में खाद्य सुरक्षा योजना का पिछले तीन महीनों में ही 41 हजार 825 क्विंटल गेहूं गायब हो गया। यह गेहूं ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को बांटा जाना था। बाजार भाव के अनुसार इसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है।

इसमें रसद विभाग, जिला आपूर्ति प्रबंधक और गेहूं परिवहन ठेकेदार का गठजोड़ सामने आया है। विभाग के अफसरों ने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं की। गौरतलब यह है कि यह तो सिर्फ एक जिले का मामला है। अन्य जिलों में जांच हो तो ऐसे कई मामले सामने आ सकते हैं। प्रदेश में बनी नई सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भ्रष्टाचार के खिलाफ काफी सख्त हैं। अब सरकार राज्य के सभी जिलों में जांच कराने की तैयारी में जुटी है। *(रा.प., 30. 12.23 एवं 31.12.23)*

कम होती जा रही खेती की जमीन

देश के उद्योग, खदान और बड़ी-बड़ी सड़क परियोजनाएं कृषि योग्य भूमि को लगातार निगलती जा रही है। यह हम नहीं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़े बोल रहे हैं। आंकड़ों के विश्लेषण से लगता है जैसे खेत देश के विकास में बड़ी बाधा है। खासकर ऐसे खेत जिनपर बाकायदा खेती होती है।

आंकड़ों पर गौर करें तो सामने आता है कि वर्ष 2019 से 2021 में छत्तीसगढ़ में करीब 28 हजार हेक्टेयर, राजस्थान में 11 हजार हेक्टेयर, कृषि योग्य भूमि कम हुई है। परियोजनाओं के लिए ली जाने वाली जमीन के संबंध में नियमों को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि नियमों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। राष्ट्रीय किसान नीति 2007 में कहा गया है कि राज्य औद्योगिक व निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए कम जैविक क्षमता वाली भूमि जैसे बंजर, क्षारियता, अम्लीयता इत्यादि से प्रभावित भूमियों को ही चिन्हित करें। *(रा.प., 03.10.23)*

भारत में बढ़ा जंक फूड का कारोबार

दुनियाभर के बाजार में जंक फूड का कारोबार घटा है, लेकिन भारत में यह तेजी से बढ़ रहा है। इसकी वजह है इसके विज्ञापन को लेकर सख्त और स्पष्ट कानून का अभाव। इसका फायदा ग्लोबल कंपनियां उठा रही है और भारत में जंक फूड उद्योग में निवेश बढ़ाने के साथ विज्ञापन के जरिए लोगों को लुभा रही है। निवेश, बैंकिंग सर्विस फर्म 'एवेंडस कैपिटल' द्वारा जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता जंक फूड मार्केट है और वर्ष 2026 तक 2.49 लाख करोड़ रुपए का जंक फूड कारोबार होने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार जंक फूड व डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के उपभोग से मानसिक स्वास्थ्य का जोखिम ज्यादा रहता है। इससे चिंता, अवसाद, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के साथ ही पेट से संबंधित कई गंभीर बीमारियों और मोटापे का खतरा ज्यादा होता है। *(दै.भा., 04.11.23)*

उपभोक्ता ढूंढ रहे पुराने बिजली बिल

गहलोत सरकार ने महंगाई राहत कैंप में रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को 562 से 1427 रुपए की सब्सिडी दी लेकिन डिस्काम ने उपभोक्ताओं के खातों की ऑडिट करवा दी। जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम ने दो बिजली खातों में बकाया राशि निकाल दी और बिलों में 1000 हजार से 5000 रुपए तक जोड़ दिए।

अफसरों की इस लापरवाही से मुख्यमंत्री निःशुल्क घरेलू बिजली योजना से हुए फायदे से ज्यादा ऑडिट की राशि चुकानी पड़ रही है। ऑडिट में 2019 से 2021 यानी तीन साल पुराने बकाया बताए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं को अब तीन साल में जमा कराए बिल व जमा की रसीद खोजनी पड़ रही है। अफसरों की गलती का खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। *(दै.भा., 03.11.23)*

प्रदेश के खजाने पर कर्ज की मार

प्रदेश के खजाने पर करीब पांच लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए घोषणाएं करने में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पीछे नहीं रहे। राजस्व बढ़ाकर घाटा कम करने का कोई मंत्र राजनीतिक दल ने नहीं दिया। जिससे ये जनहितकारी कम तथा वोट दिलाने वाली अधिक दिख रही है।

अब नई सरकार के लिए घोषणाओं के अंबार को पूरा करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। सवाल यह है कि घोषणाओं को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा। कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज ही लेना होगा।

वित्तीय प्रबंधन की सोच अपनाए बिना वोट के लिए घोषणाएं करना समझदारी नहीं मानी जा सकती। आमजनों और विशेषज्ञों को इस बाबत सवाल उठाने चाहिए। विधायक जनता के सच्चे प्रतिनिधि हों तो वित्तीय प्रबंधन के लिए विधानसभा में वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाएं। *(रा.प., 30.11.23)*

कर्ज के जाल में फंसते जा रहे राज्य

कर्ज लेकर मुफ्त की योजनाओं पर धन खर्च करने से कई राज्य कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। हाल ही चुनाव वाले पांच राज्यों में अर्थव्यवस्था से संबंधित नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक (कैग) के आंकड़ों के अध्ययन से यह स्थिति सामने आई है।

हाल यह है कि कुछ राज्यों में तो हर साल लिए जा रहे कर्ज का आधे से ज्यादा हिस्सा तो पूर्व में लिए गए कर्ज के ब्याज को चुकाने में जा रहा है। इसके अलावा ब्याज का भार भी साल दर साल बढ़ता जा रहा है।

अर्थशास्त्री सवाल उठा रहे हैं कि ज्यादातर सरकारें कर्ज को उत्पादकता बढ़ाने में खर्च नहीं कर रही है। यदि कर्ज को उत्पादक कार्यों में खर्च किया जाता है तो कर्ज बोझ साबित नहीं होता। क्योंकि, इससे राज्य की आय बढ़ती है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग की व्यवस्था करें। *(रा.प., 02.10.23, 03.10.23)*

प्रदेश में गांव पगडंडियों के सहारे

आज भी प्रदेश में कई गांव पगडंडियों के सहारे चल रहे हैं। डांग क्षेत्र में महिला को सांप ने डसा पगडंडी के सहारे अस्पताल पहुंचने में देरी से हुई मौत?, बारां-अटरू आदिवासी इलाका-मानसून में कई गांवों के बच्चों की पार्वती नदी के रपट के चलते कट जाने से तीन महीने पढ़ाई ठप्प? ऐसे कई उदाहरण गिनाए जा सकते हैं।

प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले सड़कों की यह हकीकत दैनिक भास्कर ने जुटाई है । राजस्थान के 4762 गांवों को आज भी एक सड़क का इंतजार है। 2.85 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों वाले प्रदेश में लाखों लोग आज भी पगडंडियों और उबड़-खाबड़ रास्ते के भरोसे जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके चलते आधुनिक दौर में भी ये लोग शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा जैसी कई मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आदिवासी इलाकों के कई गांव सड़कों का इंतजार कर रहे हैं। *(दै.भा., 29.10.23)*

सतत् विकास लक्ष्यों की योजना

हम दुनिया का कायाकल्प करने की दहलीज पर खड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत् विकास लक्ष्यों की ऐतिहासिक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक सम्पन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना है। सतत् विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्रवाई के लिए प्रेरित किया जाएगा।

गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाली, लैंगिक समानता, जल एवं स्वच्छता, ऊर्जा, आर्थिक वृद्धि और उत्कृष्ट कार्य, बुनियादी सुविधाएं, उद्योग एवं नवाचार, असमानताओं में कमी, संवहनीय शहर, उपभोग व उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक प्रणालियां, शांति एवं न्याय और भागीदारी।

दिखने लगा हैं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव

जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वॉर्मिंग के विषम प्रभाव दिखना शुरू हो गए हैं। खासतौर पर ठंडे देशों में इसका असर सबसे अधिक नजर आ रहा है। न्यूयॉर्क में पिछले दिनों आई बाढ़ हो या फ्रांस में खटमलों का प्रकोप और स्विटजरलेंड के विख्यात ग्लेशियर का तेजी से पिघलना, सबका कारण जलवायु परिवर्तन ही है।

न्यूयॉर्क शहर में मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ का कारण जलवायु परिवर्तन ही माना गया है। गौरतलब है कि न्यूयॉर्क में इस बाढ़ के चलते छह दिनों का आपातकाल घोषित करना पड़ा था। फ्रांस में दो सालों से औसत तापमान में लगातार परिवर्तन आया है। सितंबर माह में औसत तापमान 3 से 4 डिग्री ज्यादा रहा। वहां खटमलों के प्रकोप का कारण रिकॉर्ड गर्मी को भी बताया जा रहा है।

दरअसल गर्म मौसम खटमलों के प्रजनन के लिए बेहतर माना गया है। ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से भारत में हिमालय भी अछूता नहीं हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि सदी के आखिर में हिमालय की 75 प्रतिशत बर्फ पिंघल जाएगी। पृथ्वी के करोड़ों जीव-जन्तुओं पर इसके भीषण दुष्परिणाम का अनुमान तबाही से कम नहीं बताया जा रहा है। *(रा.प., 02.10.23)*

मिलता रहेगा गरीबों को मुफ्त राशन

केंद्र सरकार ने 80 करोड़ जरूरतमंदों तक मुफ्त राशन पहुंचाने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच साल तक जारी रखने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह जानकारी देते हुए कहा, यह कोई चुनावी वादा नहीं है। यह योजना पहले से चल रही है। इसकी अवधि दिसंबर 2023 में खत्म हो रही है। योजना के तहत हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और एक किलो चना दाल अभी भी जरूरतमंद लोगों को दी जा रही है। जरूरतमंदों को अच्छी चिकित्सा के साथ सस्ती दवाई मिले इस मकसद से जन औषधि केंद्र भी खोले गए हैं। *(रा.प. एवं दै.भा., 05.11.23)*

कृषि प्रसंस्करण में बढ़ी किसान भागीदारी

कृषि प्रसंस्करण उद्योगों में किसानों की भागीदारी बढ़ रही है। प्रदेश में कृषि उद्योग के लिए वर्ष 2024 में 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग हुई है। आने वाले साल में यह बढ़कर 6000 करोड़ रुपए पहुंचने की उम्मीद है। कृषि उद्योग में ये निवेश राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का नतीजा है। नए निवेश से कई रोजगार पैदा हो रहे हैं।

प्रदेश अब कृषि उत्पादों के उत्पादन और निर्यात का केंद्र बन गया है। नीति का लाभ उठाकर किसान अपनी फसल को खेत के निकट ही स्टोर कर उसकी कीमत बढ़ा रहे हैं। इससे किसानों को फसल की बेहतर कीमत मिलने लगी है। *(रा.प., 26.12.23)*

'वसुधैव कुटुंबकम' की मान्यता

संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 'वसुधैव कुटुंबकम' पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (आइसीसीआर) के अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि इस दर्शन का संदर्भ केवल भारतीय नहीं, इसका दृष्टिकोण वैश्विक है।

उन्होंने कहा, वसुधैव कुटुंबकम को लेकर यह ऐतिहासिक है कि इस पर यहां चर्चा हो रही है, जहां इसकी बहुत जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि एक विश्व, एक परिवार की अवधारणा एकजुटता और एकता के सिद्धांतों से मेल खाती है। *(रा.प., 12.10.23)*

गरीबी घटी, आर्थिक असमानता बढ़ी

भारत अब धीरे-धीरे हाई इनकम वाले देशों में शुमार हो रहा है। देश में गरीबी घटी है और प्रति व्यक्ति आय में पिछले 22 साल में 440 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। वर्ष 2000 से लेकर 2022 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति आय 442 डॉलर से बढ़कर 2389 डॉलर पर जा पहुंची है।

लेकिन चिंता की बात यह है कि आय और संपत्ति में असमानता यानी आर्थिक असमानता में भी भारी इजाफा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की एशिया-पैसेफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 10 प्रतिशत अमीरों की देश की कुल संपत्ति में 65 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वहीं राष्ट्रीय आय में इन 10 फीसदी लोगों की हिस्सेदारी 57 प्रतिशत से अधिक है। देश में 18.50 करोड़ लोग गरीबी में रहने को मजबूर हैं, जिनकी आय 2.15 डॉलर यानी 180 रुपए से भी कम है। *(रा.प., 08.11.23)*

जलवायु परिवर्तन: निपटने को लक्ष्य तय

विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन (कॉप-28) के समापन से दो दिन पहले वार्ताकारों ने एक महत्वपूर्ण मसौदा दस्तावेज जारी किया। इसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सभी देशों के लक्ष्य और उनकी निगरानी की रूपरेखा तय की गई है। मसौदा दस्तावेज में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों के लिए जरूरी फंडिंग अपर्याप्त है। लेकिन इसमें अनुकूलन के लिए उपलब्ध राशि और आवश्यक फंडिंग के बीच अंतर का उल्लेख नहीं है।

पिछले महीने जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में जलवायु अनुकूलन के लिए हर वर्ष 215-387 अरब डॉलर की आवश्यकता है। वित्त पोषण की इस कमी से गरीब और विकासशील देश निराश है।

(रा.प. एवं दै.भा., 11.12.23)

काले धन के मकड़जाल को तोड़ना कठिन

मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन शोधन की गैर कानूनी राह से हर साल विदेशों में जीडीपी का पांच प्रतिशत पहुंच रहा है। अगर जीडीपी 0.2 से 0.4 घट या बढ़ जाती है तो देश विदेश में वह चर्चा का विषय होती है। यह भी दावा किया जाता है कि नोटबंदी और डिजिटाइजेशन के बाद काले धन पर अंकुश लगा है।

लेकिन यूएन के ड्रग्स एंड क्राइम आफिस के अनुसार वर्ष 2021-22 में जब भारत की जीडीपी तीन ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा थी तो उसी साल 159 अरब डॉलर (करीब 10 लाख करोड़ रुपए) यानी उसका पांच प्रतिशत विदेशों में 'काले धन को सफेद' करने के लिए पहुंच गया था। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह खाने वाला यह आंकड़ा काफी डरावना है। फिक्की संचालित एक अन्य संस्था बताती है कि 122 देशों के औसत से भारत में गैर-कानूनी व्यापार, ड्रग्स, हथियार, आतंकवाद और संगठित अपराध ज्यादा हैं।

अध्ययन के अनुसार वर्ष 2009 में शीर्ष पर पहुंचने के बाद वर्ष 2014 तक इसमें कमी आई। लेकिन अगले चार वर्षों में यानी वर्ष 2018 तक लगातार बढ़ता रहा। इसी काल में फर्जी इनवॉइस के जरिए आयात-निर्यात करके एक लाख करोड़ रुपए की टैक्स चोरी हो गई। वर्ष 2014 के आम चुनाव में काला धन बड़ा मुद्दा था। लेकिन काला धन का मकड़जाल इतना जबरदस्त है कि इसे तोड़ पाना तो दूर कम करना तक मुश्किल है।

(दै.भा., 03.10.23)

भ्रष्टाचार में राजस्थान व महाराष्ट्र आगे

देश में भ्रष्टाचार के मामलों में 10.5 प्रतिशत के उछाल के साथ 4,139 मामले दर्ज हुए। वर्ष 2022 में राजस्थान और महाराष्ट्र सबसे ऊपर रहे। यह लगातार तीसरा साल है, जब दोनों राज्य इस मामले में आगे हैं। महाराष्ट्र 2021 की तुलना में 3.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 773 केस दर्ज हुए हैं।

राजस्थान में भी 2 प्रतिशत के इजाफे के साथ 511 केस सामने आए हैं। कर्नाटक 389 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। मध्यप्रदेश में 294 केस, गुजरात में176 केस और हरियाणा में 246 केस मिले हैं। *(रा.प., 06.12.23)*

समय से पहले लौटा दी सिक्योरिटी

उदयपुर विकास प्राधिकरण (तत्कालीन यूआइटी) में टेंडर शर्तों के विपरीत 18 ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का मामला सामने आया है। दरअसल, इन ठेकेदारों को समय से चार साल पहले 20 करोड़ रुपए की वर्क परफॉर्मेंस गारंटी (डब्लूपीजी) फिक्स डिपोजिट लौटा दी गई। जबकि टेंडर की शर्तों में स्पष्ट उल्लेख है कि डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड की समाप्ति के बाद ही ठेकेदार को यह राशि लौटाई जा सकती है।

एफडी को समय से पहले लौटाने का सीधा फायदा 9 नवंबर 2021 को 10 काम वाले टेंडर में हिस्सा लेने वाले ठेकेदारों को मिला। इसके अलावा इस अवधि के पहले और बाद में निकाले गए टेंडर के ठेकेदार भी इसमें शामिल है। यह एफडी 2022 में लौटाई गई जबकि इन्हें नवंबर 2025 में लौटाया जाना था। इस मामले में शिकायत अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो(एसीबी) तक पहुंच गई है। एसीबी अब मामले की पड़ताल कर रही है। *(दै.भा., 06.11.23)*

सांसद के ठिकानों से मिले 353 करोड़

झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों से आयकर छापों में 353 करोड़ रुपए की नकदी मिली है। इन नोटों को गिनने में पांच दिन लग गए। आयकर विभाग के अफसरों के मुताबिक यह किसी भी एजेंसी की ओर से एक ऑपरेशन में काले धन की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है।

सूत्रों ने बताया कि शराब व्यवसाय से जुड़ी कंपनी बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज और उससे जुड़े ठिकानों से बरामद की गई रकम में ज्यादातर 500 के नोट हैं। गौरतलब है कि धीरज साहू 2010 से झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को चुनाव के दौरान दिए हलफनामें में बताया था कि उनके पास 15 लाख रुपए कैश है, जबकि उनकी पत्नी व आश्रितों को मिलाकर परिवार के पास महज 27.50 लाख नकद हैं। वहीं, उनके व आश्रितों के खातों में कुल 8 करोड़ 59 लाख 24 हजार 106 रुपए जमा है। *(रा.प., 10.12.23, 11.12.23)*

सामने आया मूंग खरीद में भ्रष्टाचार

समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद में भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद हुई जांच में फलोदी क्रय-विक्रय सहकारी समिति में 2.16 करोड़ रुपए के हिसाब-किताब में गड़बड़ी सामने आई है। प्राथमिक जांच में 1.19 करोड़ रुपए का गबन मान लिया गया। समिति के तत्कालीन मैनेजर और कैशियर ने कैश बुक में एंट्री किए बगैर ही यह राशि उठा ली और अब उनके पास कोई हिसाब-किताब नहीं है।

खास बात यह है कि विधानसभा की बैठक में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए भी यह मामला उठाया था। जोधपुर के क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी प्रशान्त कल्ला की प्राथमिक जांच रिपोर्ट में सामने आने के बाद भी सहकारिता विभाग ने फिलहाल दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है और नियमों का हवाला देकर सहकारिता की धारा-55 में एक और नई जांच समिति बिठा दी है। *(रा.प., 28.10.23)*

आचरण सुधारें भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं

प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि अफसर अपना आचरण सुधारे। अफसरों के आचरण का अनुसरण अन्य कार्मिक करते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्तव्यों का शुद्धता से निर्वहन करें। सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलेगी।

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी तरह से हो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचारियों और उनके सहयोगियों को नहीं बख्शा जाएगा। राज्य सरकार संस्थागत भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु प्रतिबद्ध है। विभाग में सभी स्तरों से भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए।

(रा.प.19.12.23 एवं दै.भा., 23.12.23)

लोग मानते हैं आर्थिक हालत सुधरेगी

भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआइ) के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे के मुताबिक ज्यादातर भारतीय लोगों को भरोसा है कि अगले एक साल के दौरान देश की आर्थिक हालत में सुधार के साथ उनकी कमाई में भी सुधार होगा। देश में रोजगार की दशा भी बेहतर होगी।

सर्वे के मुताबिक जुलाई के दौरान लोगों के भरोसे में कमी आई थी, लेकिन सितंबर में भरोसे का इंडेक्स 92.2 पर पहुंच गया। यह आंकड़ा चार साल में सबसे ऊपरी स्तर पर है। सर्वे के मुताबिक 56.8 फीसदी भारतीयो ने माना है कि एक साल में देश की आर्थिक हालत में सुधार होगा। सीआइआइ के बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था पर कारोबारियों का भी भरोसा बढ़ा है। दूसरी तिमाही में इंडेक्स 67.1 था जबकि पिछले साल इसी तिमाही में इंडेक्स 62.2 पर था। *(रा.प., 09.10.23)*

देश की अर्थव्यवस्था में तेज वृद्धि

देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। प्रति व्यक्ति आय और सकल घरेलू उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके बावजूद महंगाई पर काबू पाना बड़ी चुनौती बना हुआ है। पिछले पांच साल के आंकड़ों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय में औसत 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेकिन इसी अवधि में रोजमर्रा के सामान काफी महंगे होने से आम आदमी को जितनी राहत मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली।

खाद्य पदार्थों की कीमतों में 123 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। यही हाल मेडिकल बिलों का है, जिन पर प्रति व्यक्ति आय का करीब 10 फीसदी हिस्सा खर्च हो रहा है। पिछले साल में आटा-चावल, दाल की कीमतें काफी बढ़ी हैं। *(रा.प., 28.11.23)*

युवाओं को करें नेतृत्व के लिए तैयार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया है कि भारत मौजूदा दौर में लंबी छलांग लगाएगा। आज पूरी दुनिया की नजर भारत के युवाओं पर है। युवा शक्ति परिवर्तन की वाहक भी है और लाभार्थी भी। हमें युवा पीढ़ी को इस तरह से तैयार करना है कि वह देश को नेतृत्व प्रदान करे और राष्ट्रीय हित को हर चीज से अधिक प्राथमिकता दें।

मोदी ने 'विकसित भारत 2047: युवाओं की आवाज' का आगाज करते हुए राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं के कुलपतियों, संस्थान प्रमुखों और संकाय सदस्यों को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति का रोडमैप अकेले सरकार नहीं, बल्कि पूरा राष्ट्र तय करेगा। देश के प्रत्येक नागरिक की इसमें सक्रिय भागीदारी होगी। *(रा.प., 12.12.23)*

नई सरकार ने लिए कई बड़े फैसले

मुख्यमंत्री ने पदभार संभालने के बाद अपनी पार्टी के घोषणा-पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। समयबद्ध तरीके से लागू करने का प्लान भी तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, घोषणा पत्र पर काम करते हुए वे मुद्दे हल किए जाएंगे जिनसे जनता त्रस्त थी।

नई सरकार ने पेपरलीक की जांच के लिए एसआईटी बनाने का फैसला लिया है। भविष्य में पेपरलीक न हों, यह सुनिश्चित किया जाएगा। अपराध व महिला अत्याचार बर्दास्त नहीं होंगे। संगठित अपराध खत्म करने को एंटी गैंगस्टार टास्क फोर्स बनेगी। कानून व्यवस्था सुधारना, भ्रष्टाचार मिटाना और महिला सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता रहेगी।

भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। सरकार की हर योजना का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे, इसके लिए मॉनिटरिंग की व्यवस्था होगी।

(दै.भा. एवं रा.प., 16.12.23, 17.12.23)

अच्छी योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार वाजपेयी के सपने को साकार करने की दिशा में काम करेगी।

उन्होंने आश्वस्त किया कि जनहित की किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। बल्कि योजनाओं की समीक्षा कर और ज्यादा लाभदायक बनाकर आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हमने आयुष्मान भारत योजना को 5 से 10 लाख तक बढ़ाया है। अब प्रदेश में इसे 25 लाख रुपए तक ले जाने का काम हो रहा है। निःशुल्क मिलने वाली दवाइयों में ऐसी दवाइयां भी शामिल की जाएंगी जो गंभीर बीमारियों के लिए उपयोगी हैं। *(रा.प. एवं दै.भा., 26.12.23)*

जन-जन तक पहुंचेगी जनहित योजनाएं

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि भाजपा राजस्थान को समग्र रूप से विकसित राज्य बनाने की दिशा में कार्य करेगी। केंद्र सरकार की जनहित योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचने ही नहीं दिया।

उन्होंने कहा कि राज्य का समग्र विकास होगा। सरकार का समाज कल्याण और आधारभूत सुविधाओं पर खास फोकस रहेगा। महिला अपराधों की रोकथाम, कानून व्यवस्था को सुधारना हमारी प्राथमिकता होगी।

उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है, उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया जाएगा। सरकार प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।

(रा.प., 14.12.23, 16.12.23)

स्वास्थ्य केंद्र होंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर

राजस्थान के 16752 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, हेल्थ एंड वैलनेस सेंटरों के नाम बदले जाएंगे। चुनाव पूरे होते ही राजस्थान ने केंद्र के फैसले की पालना में यह आदेश जारी किए हैं।

आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों को अब 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' कहा जाएगा। इसकी टैगलाइन भी बदल कर 'आरोग्यम परमं धनम' होगी आदेश में कहा गया है कि टैगलाइन को राज्यों की भाषा में लिखा जाएगा। प्रदेश में 16752 स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदलने पर 92.74 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

(दै.भा. एवं रा.प., 12.12.23)

पावर ग्रीनः सोलर व विंड उत्पादन बढ़ा

ग्रीन एनर्जी यानी प्रदूषण रहित ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान अग्रणी राज्य बन गया है। जनवरी से जुलाई तक प्रदेश में सोलर व विंड बिजली उत्पादन 2022 की इसी अवधि की तुलना में 4.4 टेरावाट यानी 44 लाख मेगावाट बढ़ा इससे कार्बन उत्सर्जन भी 10 प्रतिशत कम हुआ है। जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी भी घटकर 50 प्रतिशत नीचे पहुंच गई है।

दूसरी ओर सौर व पवन ऊर्जा उत्पादन 28 प्रतिशत बढ़ा है। सुखद यह है कि जनवरी से जुलाई तक प्रदेश में 1.7 गीगावाट सौर और 0.5 गीगावाट पवन ऊर्जा जोड़ी है और उत्पादन क्षमता 24 हजार मेगावाट हो गई। यह पूरे देश की सोलर व विंड एनर्जी का 20 प्रतिशत है। आस्ट्रेलिया बेस्ड वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर ने हाल में जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। *(दै.भा., 07.10.23)*

सोलर क्षेत्र में अब नई सरकार से उम्मीद

देश में कई शहर सोलर सिटी बन रहे हैं लेकिन राजस्थान में यह प्रोजेक्ट फाइलों से ही बाहर नहीं आया। अब 'डबल इंजन की सरकार' बनने के बाद तीन साल से अटके सोलर सिटी प्रोजेक्ट को गति मिलने की उम्मीद जगी है। केंद्रीय नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की सोलर सिटी योजना में प्रदेश के दो शहर जैसलमेर और पुष्कर शामिल है।

करीब तीन साल पहले केंद्र की इस योजना के तहत देश के 24 राज्यों ने 30 शहरों को चुना था। योजना के तहत राज्य में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम नोडल एजेंसी है। दरअसल केंद्र के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए अलग से कोई बजट नहीं दिया गया। चालू सौर योजनाओं के तहत बजट का उपयोग ही सौर शहर के विकास के लिए किया जाना था, इसलिए यह काम सिरे नहीं चढ़ पाया। *(रा.प., 27.12.23)*

बिजली चोरों के खिलाफ होगी कार्रवाई

प्रदेश में विधानसभा चुनावों की वजह से ठप रही विजिलेंस चैकिंग को अब बढ़ाया जाएगा ताकि बिजली चोरी करने वालों की धरपकड़ हो सके। इसके लिए जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम की विजिलेंस विंग ने प्लानिंग शुरू कर दी है। सुबह 3 से 7 बजे और शाम को 5 से 8 बजे तक विशेष चैकिंग की जाएगी।

इससे बिजली चोरों को रंगे हाथ पकड़ा जा सकेगा। बड़ी चोरी पकड़ने के लिए विजिलेंस विंग के एक्सईएन व डिप्टी एसपी को भी मौके पर भेजा जा रहा है। सभी इंजीनियरों को चैकिंग की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। हर बार चुनावी साल में 20 फीसदी से ज्यादा बिजली छीजत हो जाती है। इससे बिजली निगमों के वित्तीय घाटे पर असर पड़ता है। चोरी करने वालों के खिलाफ पुलिस एफआइआर दर्ज कराई जाएगी। *(दै.भा., 08.12.23)*

हाईकोर्ट के आदेश से मिली राहत

राजस्थान हाइकोर्ट की ओर से डिस्कॉम्स के स्पेशल फ्यूल सरचार्ज में ब्याज और कैरिंग चार्ज नहीं वसूलने के आदेश के बाद प्रदेश के 1.50 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। इससे एक सामान्य उपभोक्ता को 800 से 3000 रुपए (300 से 1100 यूनिट खपत वाले घरेलू उपभोक्ता) की बचत होगी।

कॅामर्शियल और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के तो हजारों रुपए बचेंगे। इस आदेश से राज्य सरकार पर जनता को राहत देने का दबाव बन गया है। गौरतलब है कि डिस्कॉम ने अडानी परिवार को कोयला भुगतान मामले में 10286 करोड़ रुपए चुकाए। इसमें 4810 करोड़ रुपए तो सिर्फ ब्याज व कैरिंग चार्ज के थे। *(रा.प., 11.11.23)*

बिजली पर टैक्स लगाने का हक

केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि उनके पास किसी भी स्रोत से उत्पन्न बिजली पर टैक्स या कोई अन्य शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है। राज्यों की ओर से इस तरह का कोई भी शुल्क लगाना गैरकानूनी और असंवैधानिक है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस बाबत सर्कूलर जारी किया है।

मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि राज्यों ने विकास शुल्क/कोष की आड़ में विभिन्न स्रोतों से बिजली उत्पादन पर शुल्क लगा लिया है। लेकिन राजस्थान सरकार ने इस रोक का तोड़ निकाल लिया है।

अब शुल्क को बिजली उत्पादन से हटाकर जमीन से जोड़ दिया गया। नई पॉलिसी में नाम बदल कर राजस्थान एनर्जी डवलपमेंट एंड फैसिलिएशन चार्ज (आरईडीएफसी) कर दिया है। अब इससे मौजूदा प्रोजेक्ट्स से करीब 142 करोड़ रुपए सालाना वसूलेंगे। *(दै.भा. 30.10.23 एवं रा.प., 31.10.23)*

विद्युत तंत्र सुधारने का यह कैसा दावा

राजधानी जयपुर समेत राज्य के ज्यादातर शहरों में मेंटीनेंस के नाम पर मनमाने तरीके से बिजली कटौती की जा रही है। जबकि राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कटौती के लिए दो दिन तय कर रखे हैं। इसके बावजूद त्योहारों के नाम पर तो कभी एलटी मेंटीनेंस के लिए आए दिन कई बार कटौती कर रहे हैं।

शहर में डिस्कॉम इंजीनियर विद्युत सुधार की बात कर रहे हैं लेकिन हकीकत में सुधार कागजों में ही हुआ है। शहर का अधिकतर हिस्सा बिजली के तारों में उलझकर रह गया है। बिजली के खंभों पर झूलते हुए तार आसानी से देखे जा सकते हैं। इससे पल-पल हादसे का अंदेशा रहता है। *(रा.प., 20.11.23, 10.12.23)*

सस्ती बिजली की बनेगी कार्ययोजना

प्रदेश में सस्ती व निर्बाध बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऊर्जा विभाग व बिजली निगमों के अधिकारियों की बैठक ली। मुख्यमंत्री ने विभाग की पहली समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए दीर्घकालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्ययोजना बनाने को कहा है।

उन्होंने अधिकारियों को अक्षय ऊर्जा की संभावनाओं को लेकर विस्तृत स्टडी कर प्लानिंग करने, बिजली छीजत घटाने को प्राथमिकता देते हुए न्यूनतम करने का लक्ष्य हासिल करने और प्रदेश में न्यूनतम मूल्य पर बिजली सप्लाई करने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। *(दै.भा.,21.12.23)*

सत्ता बदलते ही ईआरसीपी पर काम तेज

राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होते ही अब पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना(ईआरसीपी) के विवाद के भी खत्म होने के आसार बन गए हैं। यह परियोजना अब नदी जोड़ो प्रोजेक्ट के तहत आगे बढ़ेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत चंबल, पार्वती, कालीसिंध को आपस में जोड़ा जाएगा। इस परियोजना की लागत 45 हजार करोड़ रुपए आंकी गई है।

यह सब सकारात्मक रहा तो इस प्रोजेक्ट लागत की 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार वहन करेगी। बाकी 10 प्रतिशत राशि राजस्थान और मध्यप्रदेश में बंटेगी। दस प्रतिशत के हिसाब से दोनों राज्यों को 4500 करोड़ रुपए देने होंगे। इसके लिए नई दिल्ली में जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक होगी। इसमें राजस्थान और मध्यप्रदेश दोनों राज्यों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। ड्राफ्ट एमओयू पर लम्बी मंत्रणा होगी। संभव है इससे प्रदेश के 13 जिलों की पेयजल और सिंचाई की बड़ी समस्या दूर हो सकेगी। *(रा.प., 27.12.23)*

पानी के बिलों का वितरण हुआ बेपटरी

जयपुर शहर में पानी के बिल वितरण की व्यवस्था में कई तरह की खामियां नजर आ रही हैं। जलदाय विभाग ने पहले तो कई वर्षों तक बिल नहीं दिए और अब उपभोक्ताओं को हजारों रुपए के बिल थमा दिए हैं। इतनी ज्यादा राशि के बिल आने से उपभोक्ताओं में रोष व्याप्त है।

जयसिंहपुरा खोर की वीर वाटिका कॉलोनी क्षेत्र के पेयजल उपभोक्ताओं ने परेशानी बताते हुए कहा कि खोर क्षेत्र में वर्ष 2015 से पानी के बिल नहीं बंटे। कभी कभार एक-दो उपभोक्ता जलदाय कार्यालय से अपना बिल लेकर आते हैं और जमा कराते हैं। लापरवाही यह है कि पानी के बिल वीर बाटिका कॉलोनी की एक दुकान पर रखवा दिए। किसी उपभोक्ता को पता चला और किसी को नहीं चला। जबकि शहर के अन्य इलाकों में उपभोक्ताओं को घर तक पानी के बिल पहुंचते हैं। *(रा.प., 30.11.23)*

नदियों को जोड़ने से होगी बारिश कम

देश की कई नदियों को जोड़ने और सिंचाई के लिए पानी की बड़ी मात्रा को मोड़ने की एक विशाल योजना बनाई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना के कारण पहले से ही जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में बारिश कम हो सकती है। योजना का उद्देश्य सिंचाई के तहत उपजाऊ क्षेत्र को 35 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाना है।

नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार पानी को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाने से भारतीय मानसून को चलाने वाली जलवायु प्रणालियां प्रभावित हो सकती है। इससे देश के कुछ राज्यों में बारिश 12 फीसदी तक कम हो सकती है। अधिक फसलें उगाने से उनकी पत्तियों से वाष्पीकरण उत्सर्जन प्रक्रिया में उच्च स्तर पर नमी निकलेगी। इससे स्थानीय स्तर पर बारिश के पैटर्न और बादलों के निर्माण में बदलाव आएगा। कम बारिश के कारण नदियों में प्रवाह कम हो जाएगा। इससे राजस्थान व गुजरात जैसे शुष्क क्षेत्रों में पानी की कमी हो सकती है। *(दै.भा., 25.10.23)*

गर्मियों में हो सकती है पेयजल किल्लत

प्रदेश में इस बार मानसून कमजोर रहा और बीसलपुर बांध में पानी की आवक कम रही। बांध की क्षमता 315.50 आरएल मीटर है। मानसून सीजन में बांध में 313.76 आरएल मीटर तक पानी आया। फिलहाल सर्दियों में भले ही पानी की जरूरत कम होगी, लेकिन गर्मियों में शहरवासियों को पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ सकता है।

बीसलपुर बांध से जयपुर, अजमेर और टोंक शहर की एक करोड़ से अधिक आबादी को पानी की सप्लाई होती है। बांध से प्रतिदिन 2 सेंटीमीटर पानी इन शहरों की पेयजल व्यवस्था के काम आ रहा है। इस कारण बांध रीत रहा है। जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों का कहना है कि पांच महीने बाद बांध से पेयजल सप्लाई पर असर पड़ सकता है।अभी बीसलपुर बांध से जयपुर के लिए 500 एमएलडी पानी प्रतिदिन सप्लाई किया जा रहा है। गर्मियों में प्रतिदिन 600 एमएलडी से ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। *(रा.प., 08.11.23)*

कागजों में घूमती रही अमृत योजना

राजस्थान में केंद्र की अमृत योजना बस कागजों में ही घूमती रही। नगरीय विकास विभाग से जलदाय विभाग। जलदाय विभाग से प्रोजेक्ट छीनकर फिर यूडीएच। अब यूडीएच से रुडसिको एजेंसी को ट्रांसफर। इस तरह बीत गए दो साल। प्रदेश में पिछले दो साल से अमृत योजना का काम लगभग ठप पड़ा रहा।

प्रदेश के 178 शहर-कस्बों में पेयजल और सीवरेज के 200 से अधिक प्रोजेक्ट अब तक पूरे किए जाने थे, लेकिन डीपीआर तक नहीं बनाई गई। करीब 42 लाख की आबादी को कवर किया जाना था और 8.43 लाख नल कनेक्शन दिए जाने थे। इस पर करीब 5500 करोड़ रुपए के काम पूरे होने थे। लेकिन योजना के द्वितीय चरण अमृत-2.0 की पालना में राजस्थान देश में सबसे पीछे है। प्रदेश के मुख्य सचिव ने अफसरों की खिंचाई भी की लेकिन विकास का अमृत फाइलों से बाहर ही नहीं निकला। *(दै.भा., 28.12.23)*

भारत में भूजल खतरनाक स्तर पर

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगले दो साल में भारत में भूजल के स्तर में बेहद कमी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण कुछ इलाके पहले से ही खतरनाक स्तर को पार कर चुके हैं। उत्तर-पश्चिमी भारत में 2025 तक भूजल में और कमी आ सकती है।

संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय-पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है। पानी की कमी होने पर कृषि के लिए करीब 70 फीसदी पानी की निकासी भूजल से की जाती है। यदि पानी और नीचे चला गया तो कि सान पानी तक की पहुंच खो सकते हैं। इस गंभीर खतरे को देखते हुए भारत में पानी के संरक्षण और जल पुनर्भरण के लिए बड़े पैमाने पर काम करने की आवश्यकता है। *(रा.प., 27.10.23)*

हर महिला हो सबला और सशक्त

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने जैसलमेर में लखपति दीदी कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा है कि कोई भी देश अपनी आधी आबादी की उपेक्षा कर आगे नहीं बढ़ सकता है। यदि महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर हो तो भारत की जीडीपी में भी बढ़ोतरी हो सकती है।

उन्होंने कहा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का हमारा लक्ष्य है और इसके लिए हर महिला को सबल और सशक्त होना आवश्यक है। स्वयं सहायता समूह वंचित तबके को खासतौर पर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि महिला वह शक्ति है जो पूरे विश्व का हित सोचती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 11.24 लाख महिलाओं को लखपति दीदी योजना से लाभान्वित किया जाएगा। .

(रा.प. एवं दै.भा., 24.12.23)

शिक्षा पर होता है सर्वाधिक खर्च

आम लोगों की मासिक आय का बड़ा हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर खर्च होता है। करीब 65 फीसदी लोग मानते हैं कि वह सर्वाधिक शिक्षा पर खर्च करते हैं। वहीं 94 फीसदी लोगों का मानना है कि पढ़ाई महंगी हुई है। करीब 33 फीसदी लोगों ने कहा कि उन्हें बच्चों की पढ़ाई के लिए ऋण लेना पड़ा।

यह सामने आया है पत्रिका की ओर से लोगों द्वारा ऋण लेने की परिस्थितियों पर कराए गए एक ऑनलाइन सर्वे में। सर्वे के मुताबिक 25 फीसदी लोग घर बनाने और 22 फीसदी ने चिकित्सा सेवाओं के लिए ऋण लिया। करीब 62 फीसदी लोगों ने माना कि उनकी मासिक आय उनके खर्चों से कम है। वहीं 78 फीसदी लोगों का मानना है कि घर खर्च को पूरा करने के लिए पति-पत्नी दोनों को जॉब करना जरूरी हो गया है। करीब 58 फीसदी ने पार्ट टाइम काम करने की बात भी स्वीकारी है।

(रा.प., 02.10.23)

महिलाएं होंगी नेतृत्व में सक्षम

महिलाओं ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। उनमें कुशल नेतृत्व, उद्यमिता और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के गुण हैं। तीन दशक बाद पारित महिला आरक्षण बिल से उन्हें जल्द संसद और विधानसभा में बराबरी का हक मिलने वाला है। अब इसकी ताकत से वह देश को विकसित बनाने में योगदान दे सकेगी।

उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अजमेर के मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि यह बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा, विज्ञान व वाणिज्यिक क्षेत्र में देश ने जबरदस्त तरक्की की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राचीन संस्कृति, सामाजिक-उद्यमिता व कौशल विकास पर जोर दिया गया है। यह उन्हें आत्मनिर्भर, उन्नत और सामाजिक तौर पर मजबूत बनाने में सहायक होगी।

(रा.प., 09.11.23)

श्रमशक्ति में बढ़ी महिला भागीदारी

देश की श्रमशक्ति में महिलाओं की भागीदारी एक साल में 4.2 प्रतिशत बढ़कर 37 प्रतिशत हो गई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण के लिए हो रहे प्रयासों के चलते यह बढ़ोतरी हुई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बालिका शिक्षा, दक्षता उन्नयन, उद्यमशीलता और कार्यस्थलों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए किए जा रहे पर्याप्त उपायों की इसमें खास भूमिका रही है। वर्ष 2017-18 में यह संख्या 23.3 फीसदी थी। सबसे अधिक बढ़ोतरी 2019-20 के दौरान हुई है। *(दै.भा., 15.10.23)*

स्वयं सहायता समूहों को मिलेंगे ड्रोन

केंद्र सरकार अगले चार सालों में 15 हजार महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराएगी। यह ड्रोन 2023-24 और 2025-26 के दौरान दिए जाएंगे। एसएचजी महिला पायलटों के जरिए इसे खेती के लिए किसानों को किराए पर दे सकेंगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई है। अगले चार वर्षों की इस योजना पर 1,261 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस योजना से एसएचजी से जुड़ी लगभग 10 करोड़ महिलाएं एग्री-टेक का हिस्सा बन सकेंगी। ड्रोन की लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम 8 लाख रुपए तक केंद्र सरकार वहन करेगी।

(दै.भा., 30.11.23)

शिशु मृत्यु दर का बड़ा कारण प्रदूषण

लगातार बढ़ता वायु प्रदूषण नवजात शिशुओं की सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। मां के गर्भ में भी बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं। जहरीली हवा के कारण जन्मजात विकृतियों के साथ दीर्घकालीक कुप्रभाव का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है। प्रदेश में वायु प्रदूषण जनित बीमारियों से हर साल करीब 19 हजार शिशु दम तोड़ रहे हैं।

पिछले कुछ वर्षों में वायु प्रदूषण शिशु मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण बनकर उभरा है। भारत में वायु प्रदूषण से हर पांच मिनट में एक नवजात और हर तीन मिनट में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे की मौत हो जाती है। शिशुओं में हानिकारक पीएम 2.5 के कण श्वांस के जरिए रक्त प्रवाह में जा रहे हैं। इससे नवजात में बीमारियां भी तेजी से बढ़ी है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ.अशोक गुप्ता का कहना है कि यह समस्या सिर्फ मौसमी नहीं, पूरे साल एक समान है। *(रा.प., 17.12.23)*

कुपोषण- जवाबदेह कौन?

सरकार महिलाओं एवं बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए कई योजनाएं बनाती है, लेकिन उनका सही लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा। प्रदेश में आंगनबाड़ी, जननी शिशु सुरक्षा, स्कूलों में मध्या भोजन जैसी कई योजनाओं के माध्यम से बच्चों को पोषाहार दिए जाने की व्यवस्था है।

लेकिन इनमें पर्याप्त निरीक्षण व्यवस्था और जवाबदेही नहीं होने से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। नतीजतन माताओं एवं बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों व गर्भवती महिलाओं को दिया जा रहा पैकेटबंद पोषाहार लाभार्थी लेने से ही इनकार कर रहे हैं।

(रा.प., 07.10.23 एवं दै.भा., 16.12.23)

रोड एक्सीडेंट ट्रेंड पर सरकार की रिपोर्ट

देश में खड़े वाहन से टक्कर के मामले एक साल में सबसे ज्यादा 22 प्रतिशत बढ़े हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने साल 2022 में हुए एक्सीडेंट को लेकर रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक, इसके बाद हिट फ्रॉम साइड एक्सीडेंट के मामले हैं। ऐसे एक्सीडेंट की संख्या एक साल में 18.1 प्रतिशत बढ़कर 71,146 हो गई है। आमने- सामने की टक्कर 2.1 प्रतिशत बढ़ी है।

हालांकि यह एक्सीडेंट का दूसरा सबसे बड़ा प्रकार है। वर्ष 2022 में आमने-सामने की टक्कर के 77,886 मामले सामने आए हैं। साल 2022 में कुल दुर्घटनाओं में पीछे से टक्कर के मामलों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 21.4 प्रतिशत रही और यह 2021 के मुकाबले(21.2 प्रतिशत) बढ़ी है।

वर्ष 2022 में हर 100 एक्सीडेंट में 36 मौतें हुई। चंडीगढ़, मप्र, दिल्ली बेहतर रहे। बिहार, पंजाब, झारखंड, यूपी, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में इस औसत से अधिक मौतें हुईं। रेड लाइट जम्प करने के मामले सबसे ज्यादा 82.5 प्रतिशत बढ़े। *(दै.भा., 02.11.23)*

हादसेः घायलों का कैशलेस इलाज

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अगले तीन-चार महीनों में सड़क हादसों में घायलों को देशभर में कैशलेस इलाज की सुविधा देने की तैयारी कर रहा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव अनुराग जैन ने यह जानकारी देते हुए कहा कि सड़क हादसों में घायलों को मुफ्त व कैशलेस चिकित्सा सुविधा कराना संशोधित मोटर वाहन अधिनियम-2019 का हिस्सा है।

कुछ राज्यों में इसे लागू किया गया है, लेकिन अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर सड़क परिवहन मंत्रालय इसे देशभर में लागू करने जा रहा है। जैन ने बताया कि योजना के तहत पीड़ितों को नजदीकी अस्पताल में कैशलेस ट्रॉमा देखभाल की सुविधा दी जाएगी। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप होगा। कैशलेस इलाज नजदीकी अस्पतालों में गोल्डन ऑवर के दौरान मिलेगा। गोल्डन ऑवर हादसे के एक घंटे तक की अवधि को माना जाता है। *(रा.प., 05.12.23)*

चौराहों पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां

राजधानी जयपुर शहर में ऐसे कई चौराहे हैं, जहां पर ट्रैफिक नियमों की पालना के लिए बने संकेतक ही मिट गए हैं या धुंधले हो गए, जो दूर से दिखते ही नहीं हैं। वहीं कई जगह पर ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही की वजह से वाहन चालक सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

इससे नियमों की पालना कर रहे वाहन चालकों के साथ-साथ पैदल सड़क पार करने वाले राहगीरों को भी इससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे हादसों का खतरा बना रहता है। पुलिस केवल बिना हेलमेट वालों के चालान काटने में व्यस्त रहती है। जबकि उनकी आंखों के सामने से लोग ट्रैफिक नियमों को धता बता रहे हैं।

लोग रेड लाइट होने पर वाहनों के बीच से पैदल निकल रहे हैं। रेड लाइट होने पर वाहनों को स्टॉप लाइन से पहले रोकना होता है, लेकिन वे जेब्रा क्रॉसिंग पर वाहन रोकते है। जेब्रा क्रॉसिंग खाली नहीं होने के कारण पैदल चलने वाले राहगीर बीच -बचाव कर चौराहा पार करते दिखाई देते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी स्टूडेंट्स, बुजुर्ग और महिलाओं को होती है। *(दै.भा., 30.10.23)*

सड़क हादसों में हम 9वें नम्बर पर

सड़क दुर्घटनाओं में राजस्थान देश में 9वें नंबर पर है जबकि मौतों में प्रदेश का 5वां स्थान है। केरल के मुकाबले राजस्थान में हादसे 55 प्रतिशत कम है। जबकि ट्रोमा केयर कमजोर होने से मौतें 65 प्रतिशत ज्यादा हैं। यानी हादसों के बाद जान बचाने में राजस्थान के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं।

दुर्घटना के बाद जान बचाने के लिए सबसे जरूरी घंटे यानी 'गोल्डन ऑवर्स' में हम घायल को जरूरी इलाज देने में नाकाम रहते हैं। क्योंकि ट्रोमा केयर से जुड़ा हमारा ढांचा कमजोर व गेप वाला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 50 किमी पर ट्रोमा सेंटर जरूरी है। राज्य में हाईवे की लंबाई 12 हजार किमी है। ऐसे में यहां 240 ट्रोमा केयर सेंटर होने जरूरी है। लेकिन परिवहन विभाग के मुताबिक 57 सेंटर हैं। 30 के पास एडवांस लाइफ केयर एंबुलेंस नहीं है और 20 में एंबुलेंस ही नहीं है। *(दै.भा., 17.10.23)*

हेलमेट पहनने वालों की बची जान

आप सड़क पर दोपहिया वाहन चलाते हैं तो सावधान हो जाएं.. वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहन लें। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सड़क दुर्घटना में बिना हेलमेट पहनने वाले लोगों की अधिक मौत हुई है। जिन्होंने हेलमेट पहन रखा था, उनकी सड़क दुर्घटना में जान बच सकी।

सड़क दुर्घटनाओं के पिछले पांच वर्ष के तुलनात्मक आंकड़ों में सामने आया है कि वर्ष 2023 में मौतों का ग्राफ बढ़ा है और घायलों की संख्या में भी इजाफा हुआ है । मौत के ऐसे शिकार लोगों की तादाद बढ़ी है, जिन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था । जयपुर की बात की जाए तो अधिकतर वाहन चालक हेलमेट तो लगाते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रिप लगाने में कोताही बरतते हैं। *(रा.प., 03.11.23)*

गिग वर्कर्स को देंगे रोड सेफ्टी ट्रेनिंग

जयपुर परिवहन विभाग की ओर से राजधानी में करीब तीन हजार गिग वर्कर्स को रोड सेफ्टी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभाग की ओर से इसके लिए प्लान तैयार किया गया है। पहले चरण में जयपुर से इसकी शुरुआत हो रही है। इसके बाद दूसरे जिलों में में भी विभाग प्रशिक्षण शुरू करेगा ।

हाल ही विभाग की ओर से कैब और फूड कंपनियों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी। जिसमें गिग वर्कर्स ने विभाग की ओर से की जा रही वाहनों पर कार्रवाई पर आपत्ति जताई। तब विभाग ने कार्यवाई नहीं करने का आश्वासन दिया लेकिन अधिकारियों को हिदायत दी है कि ओवर स्पीड में बिना लाइसेंस वाहन दौड़ाने वाले गिग वर्कर्स पर कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया कि कैब कंपनी के वाहनों के लिए पंजीयन जरूरी है। *(रा.प., 22.12.23)*

उपभोक्ता फैसले

टिकट के साथ पॉप कार्न क्यों? देना होगा हर्जाना

जोधपुर निवासी अनिल भंडारी, उर्मिला भंडारी, रंजू जैन और शांतिचंद पटवा ने जिला उपभोक्ता आयोग में मिराज सिनेमा बायोस्कॉप और मिराज एंटरटेनमेंट के खिलाफ परिवाद दायर किया। परिवाद में बताया कि 24 मई 2018 को फिल्म देखने के लिए उन्होंने ऑनलाइन 140 रुपए प्रति टिकट के हिसाब से चार टिकट बुक कराए थे। सिनेमा हॉल पहुंचने पर उन्हें 90 रुपए प्रति टिकट की दर से 360 रुपए के टिकट जारी किए गए और 200 रुपए के पॉप कार्न के 4 पैकेट जबरदस्ती और नाजायज तरीके से दिए गए। जिनमें महज पांच दस रुपए के पॉप कार्न थे। ऐतराज करने पर भी पॉप कार्न खरीदना अनिवार्य बताया।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता आयोग ने मिराज सिनेमा बायोस्कॉप और मिराज एंटरटेनमेंट को दोषी माना और परिवादियों को 200 रुपए पॉप कार्न की कीमत, 20,000 रुपए बतौर हर्जाना, 5000 रुपए परिवाद व्यय कुल 25,200 रुपए दो माह की अवधि में देने के आदेश दिए हैं। साथ ही दर्शकों से मुनाफाखोरी कर जबरन पॉप कार्न बेचने के दंड स्वरूप 50 हजार रुपए उपभोक्ता कल्याण कोष में भी जमा कराने होंगे। आयोग ने इस बारे में जिला कलेक्टर को भी नाजायज वसूली के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए फैसले की प्रति भिजवाने को कहा है।

(रा.प. एवं दै.भा.,10.12.23)

बिजली मीटर की रीडिंग लिए बिना क्यों भेजा मनमाना बिल?

जयपुर स्थित जगतपुरा निवासी विनोद मेहता ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.(जेवीवीएनएल) के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर-द्वितीय में परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में आयोग को बताया गया कि उन्होंने बिजली का घरेलू कनेक्शन ले रखा है। उनके कभी भी 1000 से 1600 रुपए से ज्यादा का बिल नहीं आया, लेकिन मनमाने तरीके से जुलाई 2015 का बिल 26,890 रुपए का जारी कर दिया। उन्होंने जेवीवीएनएल के ऑफिस में जाकर अधिकारियों से बिजली मीटर की दुबारा रीडिंग लेने के लिए कहा तो उन्हें बिजली कनेक्शन काटने की धमकी दी गई। धमकी से डरकर उन्होंने बड़ी मुश्किल से बिल राशि जमा करा दी। उन्होंने आयोग से जमा कराई राशि हर्जा-खर्चा सहित वापस दिलाने का आग्रह किया।

मामले कि सुनवाई पर जेवीवीएनएल की ओर से कहा गया कि अंधेरे के चलते मीटर की रीडिंग नहीं ली जा सकी। ऐसे में औसत आधार पर बिल जारी किया गया। बिल में पुराने बिलों की राशि भी समायोजित है। उपभोक्ता आयोग ने रीडिंग लिए बिना मनमाने तरीके से बिल जारी करने को गलत और सेवा दोष माना और जेवीवीएनएल को आदेश दिया कि वह बिल की राशि 26,890 रुपए नौ फीसदी ब्याज सहित परिवादी विनोद मेहता को लौटाए। साथ ही उन्हें हुई परेशानी की एवज में 15 हजार रुपए हर्जाना भी अदा करे। *(दै.भा., 17.12.23)*

फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख तक जुर्माना

टेलीकॉम बिल 2023 लोकसभा में पास हो गया है। अब इस बिल को राज्य सभा में भेजा गया है। इस बिल में सिम कार्ड का दुरुपयोग रोकने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। फर्जी सिम लेने पर 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है।

टेलीकॉम कंपनियां बिना ई-केवाईसी के ग्राहकों को नए सिम कार्ड जारी नहीं कर सकेंगी। सिम कार्ड खरीदने के लिए बायोमेट्रिक पहचान को अनिवार्य किया गया है। यह बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क को टेकओवर, मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की अनुमति देता है। जरूरत पड़ने पर सरकार किसी भी व्यक्ति का मैसेज ट्रैक कर सकती है और ट्रांसमिशन रोक सकती है। जनहित में सरकार टेलीकॉम कंपनियों को कोई भी मैसेज भेजने का निर्देश दे सकती है। बिल में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने, फाइबर काटने, टावर तोड़ने पर 2 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और सजा का प्रावधान भी है। *(रा.प., 21.12.23)*

राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामे से निपटे लाखों मामले

नालसा के निर्देश पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) की ओर से हाल ही इस साल की चतुर्थ और आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत में हाइकोर्ट सहित प्रदेश की निचली कोर्ट, अधिकरणों, आयोगों, उपभोक्ता मंचों व रेवन्यू कोर्ट में पक्षकारों के बीच राजीनामे से एक दिन में प्रिलिटिगेशन व पेंडिंग 49 लाख 71 हजार 103 केसों का निपटारा किया गया है।

राष्ट्रीय लोक अदालत में विवादों को तय करने के लिए पक्षकार खुद मिलजुल कर अपने केसों में फैसला करते हैं। गौरतलब है कि लोक अदालत में केसों की सुनवाई के लिए हाइकोर्ट सहित निचली कोर्ट में 505 बेंच बनाई गई थीं, जिनमें उक्त मामले सुलझाए गए। राष्ट्रीय लोक अदालत में खासतौर पर राजीनामें योग्य एनआई एक्ट के चेक बाउंस केस, एंमएसीटी, श्रम व नियोजन संबंधी, भूमि विवाद और राजस्व मामलों को निस्तारण के लिए रखा गया था। *(दै.भा., 10.12.23)*

स्रोतः रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, स.ज.: समाचार जगत, रा.दू.: राष्ट्रदूत

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.228 2821
फैक्सः 228 2485, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org
यहां भी दिल्ली, कोलकता और चित्तौड़गढ़ (भारत); लुसाका (जाम्बिया); नैराबी (केन्या); आक्करा (घाना); हनोई (वियतनाम); जिनेवा (स्विटजरलैंड) और वॉशिंगटन डी.सी. (यूएसए)